



वन नेशन वन वोटर कार्ड

प्रीलिमिंस के लिये

भारतीय नरिवाचन आयोग

मेन्स के लिये

पोस्टल बैलेट की आवश्यकता व महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत नरिवाचन आयोग ने वैश्विक महामारी COVID-19 के बढ़ते जोखिम को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान करने की सुविधा प्रदान कर दी है।

प्रमुख बंदि

- भारतीय नरिवाचन आयोग द्वारा पूर्व में 80 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिकों व दवियांग नागरिकों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
- कोरोना संकट का असर आगामी **बहार वधानसभा चुनाव** में भी देखने को मलिया। सोशल डिस्टेंसिंग और बूथों पर भीड़ कम करने के लिये चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट से मतदान की आयु को 80 वर्ष से घटाकर अब 65 वर्ष कर दी है।
- केंद्र सरकार द्वारा नरिवाचन आयोग के प्रस्ताव को अनुमति देने के बाद अब 65 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ को कम करने में भी मदद मलिया।

पोस्टल बैलेट से तात्पर्य

- जो व्यक्ति किसी नरिदृष्टि सेवा में कार्यरत होने के कारण अथवा दवियांग या वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मतदान केंद्र तक पहुँचने में असमर्थ है। उन लोगों को डाकपत्र के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा देना ही पोस्टल बैलेट कहलाता है।
- भारत नरिवाचन आयोग** 'अनुपस्थिति मतदाता' की सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिये सरल तथा सहज मताधिकार प्रयोग करने की प्रकिया उपलब्ध कराने के लिये प्रतबिद्ध है। इस पहल से इस बात की आश्वस्तता बढ़ी है कि वरिष्ठ नागरिक तथा दवियांग व्यक्ति भी अपने मताधिकार का सहज रूप से प्रयोग कर सकेंगे।

प्रवासियों के मताधिकार का मुद्दा

- वभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने नरिवाचन आयोग से आग्रह किया है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मताधिकार करने की सुविधा का वसितार प्रवासी मजदूरों तक किया जाए।
- वर्ष 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, घरेलू प्रवासियों की संख्या तकरीबन 13.9 करोड़ है। यह भारत की श्रमशक्तिका लगभग एक-तहार्ई है।
- घरेलू प्रवासी श्रमिक बेहतर कार्य की तलाश में महानगरों की ओर पलायन करते हैं, उनका महानगरों में स्थायी नवास का लक्ष्य नहीं होता है परणामस्वरूप महानगरों के नरिवाचन क्षेत्र में पंजीकृत न होने के कारण वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
- जनप्रतनिधियों को चुनने में प्रवासी श्रमिकों की कोई वशेष भूमिका नहीं होती है इसलिये इस वर्ग की समस्याओं को किसी भी प्रकार की तवज्जों नहीं मलि पाती है।
- बड़ी संख्या में होने के बावजूद अपने मताधिकार का प्रयोग न कर पाने के कारण प्रवासी श्रमिकों को '**वसिमृत मतदाता**' की संज्जा दी गई है।

नरिवाचन आयोग की भूमिका

- वर्तमान में भारतीय पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 91.05 करोड़ है, जो वास्तव में गर्व का वषिय है।
- वर्ष 2019 में हुए आम चुनाव में लगभग 67.4 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नरिवाचन आयोग को अपना ध्यान 29.68 करोड़ उन मतदाताओं पर लगाना चाहिये जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।
- राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन सर्वेक्षणों से पता चला है कि लगभग 10 प्रतिशत पंजीकृत मतदाता राजनीति में रुचिकी कमी के कारण मतदान करने से बचते हैं।
- लगभग 20 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो मतदान करना चाहते हैं परंतु अनुकूल परिस्थितियाँ न होने के कारण वे मतदान नहीं कर पाते हैं। इनमें घरेलू प्रवासी और अनवासी भारतीय शामिल हैं।
- वस्तुतः अनवासी भारतीयों को मताधिकार उपलब्ध कराने के लिये नरिवाचन आयोग ने अधिकृत व्यक्ति (Authorised proxies) के माध्यम से मत देने की व्यवस्था की है।

मतदाता वहनीय सुविधाएँ

- अपने पंजीकृत नरिवाचन क्षेत्र से दूर सेवा दे रहे सरकारी कर्मचारी [इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम \(Electronically Transmitted Postal Ballot System-ETPBS\)](#) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।
- वर्गीकृत सेवा मतदाता (सैन्य कर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल) अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- नरिवाचन आयोग ने कहा है कि विह आधार-लकिड मतदान पहचान पत्र के निर्माण हेतु आवश्यक तकनीकी का परीक्षण कर रहा है। यह मतदाताओं को देश में किसी भी स्थान से डिजिटल माध्यम का प्रयोग करते हुए मतदान करने में सक्षम बनाएगा।

आगे की राह

- भारतीय नरिवाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान योग्य कोई भी व्यक्ति नरिवाचन प्रक्रिया में पीछे न छूट जाए।
- नरिवाचन आयोग को पोस्टल बैलट की सुविधा में वसितार करते हुए इसे प्रवासी श्रमिकों तक ले जाना चाहिये।
- COVID-19 संकट ने सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रवासी श्रमिकों तक पहुँचने के लिये विभिन्न पोर्टल व एप स्थापित करने के लिये प्रेरित किया है। नरिवाचन आयोग को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।
- मतदान को न केवल नागरिक कर्तव्य के रूप में देखा जाना चाहिये, बल्कि नागरिक अधिकार के रूप में भी देखा जाना चाहिये।

स्रोत: द हट्टू